## शब्दावली

## शब्दावली

पारिभाषिक शब्द	अर्थ
व्यापार निरंतरता योजना	व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) किसी भी रिकवरी रणनीति के सबसे
	महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो किसी आपदा के मामले में एक संगठित,
	सुरक्षित और समय पर रिकवरी सुनिश्चित करता है।
पेंशन/उपदान/	पेंशन लाओं की गणना, अर्हक सेवा और औसत परिलब्धियों के आधार पर की
रूपांतरण भुगतान आदेश	जाती है और भुगतान के लिए प्राधिकरण, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), उपदान भुगतान आदेश (जीपीओ) और रूपांतरण भुगतान आदेश (सीपीओ) के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
केंद्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण	केंद्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण प्रणाली (सीपीएसएमएस), लेखा महानियंत्रक
प्रणाली	कार्यालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार की योजना स्कीमों के अंतिम लाभार्थी तक निधि संवितरण का पता लगाने के लिए एक उपयुक्त ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली और निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित करना और वास्तविक समय आधार पर कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर निधि के उपयोग प्रतिवेदित करना है।
डेटा शब्दकोश	डेटा शब्दकोश एक डेटा मॉडल में डेटा विषय अथवा वस्तुओं के विवरण का
	एक संग्रह है, जिससे लोगों को यह समझने में लाभ हो सके कि डेटाबेस संरचना में एक डेटा वस्तु कहां फिट बैठता है, इसमें क्या मूल्य हो सकते हैं और मूल रूप से डेटा आइटम का वास्तविक दुनिया के संदर्भ में, क्या अर्थ है।
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी) एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसकी कुल सेवा के आधार पर किया गया एकमुश्त भुगतान है।
आपदा रिकवरी योजना	आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक आपदा रिकवरी योजना (डीआरपी) को डिज़ाइन किया जाता है।
एक्साडेटा	ऑरेकल विशेषज्ञों (ओईएम) द्वारा विन्यस्त एक सॉफ्टवेयर समाधान, जिसमें
	सीधे ओईएम से एकल बिंदु समर्थन होता है। इसके अलावा, उच्च उपलब्धता के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसकी लागत पारंपरिक तरीके से सर्वरों को विन्यस्त करने से कम है।
सरकारी व्यवसाय सॉफ्टवेयर समाधान	जीबीएसएस, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ धन का निपटान करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है।
माल एवं सेवा कर नेटवर्क	एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन जो प्रत्येक वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करता है और करदाताओं को पंजीकरण से लेकर रिटर्न फ़ाइल करने तक की सभी सेवाएं प्रदान करता है तथा सभी कर विवरणों का संधारण और जीएसटी पोर्टल की संपूर्ण आईटी प्रणाली का प्रबंधन करता है।
अंतर-विभागीय समिति	वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा एनआईसी, झारखण्ड राज्य इकाई के सदस्यों से गठित।
झारखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त एजेंसी, जैप-आईटी, झारखण्ड सरकार की आईटी एवं ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है।
निकट आपदा रिकवरी केंद्र	व्यावसायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता हेतु किसी बाधा/आपदा की स्थिति में प्रणाली के सर्वरों और एप्लीकेशनों को होस्ट कर संचालित करने के लिए किसी नजदीकी स्थान पर स्थापित एक डेटा केंद्र।

पारिभाषिक शब्द	अर्थ
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की स्थापना 1976 में केंद्र एवं राज्य
	सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से हुई और
	यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेयटी), भारत सरकार के
	तहत काम करता है।
राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार	एनएसडीएल एक वित्तीय इकाई है, जिसे सभी प्रतिभूतियों को मूर्त अथवा
लिमिटेड	गैर-भौतिक प्रमाण पत्र के रूप में रखने हेतु स्थापित किया गया है। डीमैट
	खातों के संधारण, विशेष रूप से स्टॉक एवं बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों के लिए;
	एनएसडीएल बैंक के रूप में कार्य करता है।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन	सीजीए के कार्यालय द्वारा रेखांकित, विकसित, स्वामित्व और कार्यान्वित,
प्रणाली	पीएफएमएस एक मजबूत वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली के रूप में
	विकसित हुआ है। यह भुगतान और राजकोष नियंत्रण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
	(डीबीटी), निधि प्रवाह तंत्र का अनुश्रवण, प्राप्तियों (कर तथा गैर-कर) के
	लेखांकन, लेखाओं के संकलन और राजकोषीय प्रतिवेदन तैयार करने और
	सूचना के प्रसार की स्विधा प्रदान करता है। यह राज्यों, बैंकों तथा अन्य
	बाह्य प्रणालियों के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ इंटरफेस स्थापित करता
	है।
परियोजना नेतृत्त्व दल	आईएफएमएस की एक वरिष्ठ प्रबंधन दल, जिसमें मुख्य सचिव, प्रधान वित्त
	सचिव, प्रधान आईटी सचिव, विकास आयुक्त, योजना सचिव और एनआईसी
	के राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी शामिल होते हैं।
परियोजना प्रबंधन समूह	पीएमजी की तीन इकाइयां हैं, यथा- आईटी दल, परिवर्तन दल और
	परियोजना प्रबंधन दल।
परियोजना अनुश्रवण इकाई	वित्त विभाग के अंतर्गत राज्य में कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना के
-	कार्यान्वयन हेतु एनआईसी की निगरानी में आउटसोर्स किये गए उच्च-स्तरीय
	डेवलपर्स को शामिल कर एक परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) का गठन
	किया गया (अक्टूबर 2009)।
साई-पेंशन	पेंशन और अन्य पेंशन लाभों के भुगतान के लिए प्राधिकार निर्गत करने की
	प्रक्रिया हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड के कार्यालय का पेंशन
	पोर्टल।
राज्य डेटा केंद्र	झारखण्ड राज्य डेटा केंद्र, खुले असुरक्षित सार्वजनिक डोमेन और संवेदनशील
	सरकारी वातावरण के बीच मध्यस्थ और अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य
	करता है। यह राज्य के विभिन्न विभागों को अपनी सेवाओं/एप्लीकेशनों को
	एक सामान्य अवसंरचना पर होस्ट करने में सक्षम बनाता है, जिससे
	एकीकरण और कुशल प्रबंधन में आसानी होती है।
प्रणाली डिजाइन दस्तावेज़	प्रणाली डिजाइन दस्तावेज़ (एसडीडी) सॉफ्टवेयर विकास का एक प्राथमिक
	दस्तावेज है जो सॉफ्टवेयर समाधान की बनावट का वर्णन करता है।
सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश	सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	का पूर्ण विनिर्देश और विवरण है जिसे सॉफ्टवेयर प्रणाली के सफल विकास
	के लिए पूरा करना आवश्यक है। एसआरएस एक प्रारूप प्रतिवेदन है, जो
	सॉफ्टवेयर के प्रतिनिधित्व रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को यह
	समीक्षा करने में सक्षम बनाता है कि सॉफ्टवेयर प्रणाली उनकी आवश्यकताओं
	के अनुरूप है या नहीं।
स्रोत पर कर की कटौती	सरकार के पास जमा करने हेतु भुगतानकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को भुगतान
VILLE IX TV TV TVOICH	करते समय कटौती किए गए कर का एक निश्चित प्रतिशत।
	THE WALL POOR THE STATE OF THE VALUE WILLIAM STATES

पारिभाषिक शब्द	अर्थ			
उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) सॉफ्टवेयर विकास का एक महत्वपूर्ण			
	चरण है, जहां इच्छित उपयोगकर्ता या ग्राहक वास्तविक दुनिया की स्थितियों			
	में सॉफ्टवेयर का परीक्षण करते हैं। यूएटी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है			
	कि सॉफ्टवेयर अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करता है और प्रकाशन			
	के लिए तैयार है।			
उपयोगकर्ता आवश्यकता	उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश (यूआरएस) प्रणाली से उपयोगकर्ता की			
विनिर्देश	व्यावसायिक आवश्यकताओं का वर्णन करता है। युआरएस, प्रणाली के निर्माण			
	से पहले तैयार किया जाता है।			
निर्माण लेखा प्रबंधन सूचना	निर्माण लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (वामिस) निर्माण तथा वन विभाग हेतु			
प्रणाली	एक लेखांकन सॉफ्टवेयर है, जो किसी प्रमंडल में तकनीकी अनुभाग द्वारा की			
	गई सभी गतिविधियों का व्याख्यान करता है, ताकि विभिन्न कार्यों की प्रगति			
	का अनुश्रवण इसकी शुरुआत से की जा सके।			